(c) what action has been taken thereon?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI K. C. PANT): (a) and (b) Federation of Engineering Industries of India have represented regarding uneconomic operations of mini steel plants in recent years due to increase in cost of inputs and fall in prices of finished products. The federation has requested for continuation of MODVAT scheme and abolition of custom duty on imported scrap.

(c) Government have taken steps to improve scrap availability to mini steel plants by increasing imports and reducing the level of custom duty.

Guidelines to bank for I.R.D.P. loans

2020. SHRI M. A. BABY: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that banks have not been following the guidelines set by Government regarding I.R.D.P. loans; and

(b) if so, what are the steps taken or proposed to be taken to overcome this bottleneck?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI RAMANAND YADAV): (a) Banks have, generally, been following guidelines issued for sanction of loans under IRDP. Credit support for IRDP has been satisfactory. During 1985-86 an amount of Rs. 730.15 crores has been mobilised as term credit for IRDP. During the current year. upto January 1987, an amount of Rs. 621.21 crores has been mobilised as term credit.

(b) Whenever any cases of violation of the IRDP guidelines are brought to the notice of Government, the matter is taken up with the Head Offices of the banks, Reserve Bank of India (RBI) or the National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD). Policy matters regarding credit support to IRDP are discussed in the High Level Committee on Credit. A Consultative machinery for bankers and Government officials to sort out local problems has also been set up at the State, District and Block levels.

दिल्ली में भूमि का भाव

2021. **श्री धूलेश्वर मीणा :** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उस सरकारी भूमि का भाव क्या था जिसे दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दक्षिणी दिल्ली में 1975 में जनता को बेचा था ; और

(ख) 1980 तथा 1986–87 में प्रति वर्ग मीटर बाजार भाव क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) दक्षिणी दिल्ली में 1975 में नीलाम किए गए रिहायशी प्लाटों की बाजार दर 364/-रुपये से 442/- रुपये प्रति वर्ग मीटर के बीच थी।

(ख) वर्ष 1980 में, बाजार दर 1683/-रुपये से 2182/- रुपये प्रति वर्ग मीटर के मध्य थी।

अर्नजित वृद्धि, जो 3600/- रुपये से 5000/- रुपये प्रति वर्ग मीटर थी, को वसूल करने के लिए दिल्ली प्रशासन द्वारा वर्ष 1986 में दक्षिणी दिल्ली में बाजार दर निर्धारित की गई थी।

नई दिल्ली में सनलाइट झुग्गी झोंपड़ी कालोनी में भूखंड

2022. **श्री धूलेश्वर मीणा :** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सनलाइट झुग्गी झोपड़ी कालोनी, नई दिल्ली–11 में 80 वर्ग गज के कुल कितने

प्लाट हैं और कितने आवंटित हो चुके हैं और कितनों का आवंटन बाकी है तथा उनकी संख्या कितनी है ;

(ख) क्या 80 वर्ग गज के इन प्लाटों की कीमत पुरानी दर पर निर्धारित की गई है यदि हां, तो निर्धारित कीमत कितना है;

(ग) क्या यह सच है कि 1969 में कटरा एरायन निजामुद्दीन, नई दिल्ली से बेदखल किए गए कुछ व्यक्ति चूल्हा टैक्स अदा कर रहे थे यदि हां, तो क्या उन्हें सनलाइट झुग्गी झोपड़ी कालोनी में 80 वर्ग गज के प्लाट आवंटित किए गए थे और चूल्हा टैक्स देने वालों को पट्टा प्रलेख रजिस्ट्री प्रदान करने के लिए उनसे वसूल की गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या आगे से इन लोगों के लिए पट्टा प्रलेख रजिस्ट्री दिल्ली विकास प्राधिकरण बनायेगा या दिल्ली विकास प्राधिकरण का गन्दी बस्ती तथा झुग्गी झोपड़ी स्कन्ध बनायेगा ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि सनलाईट जे०जे० कालोनी नई दिल्ली में प्रत्येक 80 वर्ग गज के 166 प्लाट काटे गए थे। इनमें से, 158 प्लाट आवंटित कर दिए गए हैं तथा 8 प्लाट बिना आवंटन के बचे हुए हैं।

(ख) और (ग) कटरा इरादत मुण्ड खान (जो कटरा अहिरान के नाम से भी जाना जाता है) में रह रहे 59 व्यक्ति चूल्हा टैक्स दे रहे थे तथा उन्हें 1969 में प्रत्येक 80 वर्ग गज के वैकल्पिक प्लाट सनलाईट कालोनी में आवंटित किए गए थे उन्हें अभी तक पट्टाधारण अधिकार नहीं दिया गया है। इन आवंटितियों से वसूल किए जाने वाली कीमत/प्रीमियम के नियतन का प्रश्न विचाराधीन है।

(घ) सनलाईट कालोनी के बारे में पट्टाविलेखों के निष्पादन का कार्य दिल्ली विकास प्राधिकरण के स्लम तथा झुग्गी झोपड़ी विभाग को सौंपा गया है।

Anti poverty programmes

2023. SHRI SUBAS MOHANTY: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) what are the details of the anti-poverty programmes that are being taken up during 1987-88;

(b) whether the target fixed for the above purpose has been fully achieved durnig the year 1986-87; and

(c) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI RAMANAND YADAV): (a) The major anti poverty programmes are Integrated Rural Development Programme (IRDP), National Rural Employment Programme (NREP) and Rural Landless Employment Guarantee Programme (RLEGP). For IRDP, an amount of Rs. 310.00 crores has been provided in the budget estimates for 1987-88. Out of this an amount of Rs. 308.14 crores has been earmarked for IRDP main programme and Rs. 1.86 crores for voluntary agencies. central cell, monitoring cells and Research and Concurrent Evaluation etc. It is targetted to assist 39.11 lakh families during 1987-88. Under NREP, funds amounting to Rs. 480.00 crores are propsed to be provided as central assistance (inclusive of value of foodgrains). Under NREP; the average rate of 290 million mandays of employment generation per annum is indicated for the Seventh Plan period. For RLEGP the provision in the budget estimates for 1987-88 is Rs. 725 crores. For this programme the average rate of 200 million mandays of employment generation per annum is indicated for the Seventh Plan period.